Clause—I

SHRI LALIT VIJAY SINGH: Sir, I beg to move;

"That at page 1, line 3, for the figure '1990' the figure '1991' be substituted. "

The question was put and the motion was adopted.

5. P. M.

श्री कपिल वर्मा : इलैक्शन कब होंगे ?

SHRI LALIT VIJAY SINGH: As already said, between September and November 1991. We require this t: me for revision of t?r? electoral rolls.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): I shall put clause 1, as amended to vote. The question

"That Clause 1, as amended, stand part of the bill. "

The motion was adopted.

Clause 1, *as amended, was added to the Bills.*

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI LALIT SINGH: i move:

"That the Bill, as amended, be passed. "

The question was put, and the motion was adopted.

STATUTORY RESOLUTION APPROVING PRESIDENT'S PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 IN RELATION TO GOA

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): We shall go to the ■ next agenda item, the Statutory Resolution. Shri Subodh Kant Sahay to move the Resolution.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : महोदय, मेरा कहना है :

"कि यह सदन संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन गोवा राज्य से संबंधित राष्ट्रपति द्वारा 14 दिसम्बर, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करता है।"

गोवा के राज्यपाल की रिपोर्ट और उद्घोषणा की प्रतियां सदन के सभा पटल पर रखी गई हैं।

गोवा के राज्यपाल ने भारत के राष्ट्रपति को सम्बोधित अपनी 11 दिसम्बर, 1990 की रिपोर्ट में गोवा में चल रही राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन किया था। राज्यपाल ने उल्लेख किया था कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एम जी पी) द्वारा मुख्य मंत्री डा लुइस प्रोटो बारबोसा से समर्थन वापस लिए जाने के कारण राज्य में राजनीतिक स्थिति अनिश्चित हो गई है। मुख्य मंत्री और भूतपूर्व उप मुख्य मंत्री दोनों ही बिना किसी निश्चित सबूत के बहुमत का दावा कर रहे हैं। राज्यपाल ने यह भी संकेत दिया था कि दोनों ग्रुपों की संख्या का सदन के पटल पर परीक्षण करने के लिए उन्होंने 4 दिन का नोटिस देकर 10 दिसम्बर, 1990 को विधान सभा का सत्र बुलाया है, ताकि वे अपने-अपने दावों को सिद्ध कर सकें। राज्यपाल ने रिपोर्ट दी कि मुख्य मंत्री ने अपनी मंत्री परिषद् के साथ 10 दिसम्बर, 1990 को प्रातः ही त्याग पत्र दे दिया था।

गोवा में चल रहे मौजूदा राजनीतिक गतिरोध के संदर्भ में राज्यपाल ने उल्लेख किया है कि कांग्रेस--ई विधान पार्टी के 13 सदस्यों, गोआन पीपल्स पार्टी के 4 सदस्यों, एम जी पी के दो सदस्यों और एक आजाद सदस्य ने 9 दिसम्बर, 1990 को एक कामन फ्रंट जिसे "कांग्रेस डेमोक्रेटिक फ्रंट" (सी डी एफ) के नाम से जाना जाता है, बना लिया है। इस फ्रंट ने गोवा विधान सभा में 9 दिसम्बर, 1990 से एक पार्टी के रूप में काम करना था। फ्रंट ने यह भी निश्चय किया कि डा० विलफ्रेड डीसूजा, कांग्रेस विधान

[श्री सुबोध कान्त सहाय]

पार्टी के नेता गोवा विधान सभा में कांग्रेस डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता होंगे।

श्री आर० डी० खलप के नेतृत्व वाला प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट 10 दिसम्बर, 1990 को राज्यपाल से मिला और उनसे श्री खलप को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया।

राज्यपाल ने स्थिति का मूल्यांकन करते हुए यह उल्लेख किया था कि कांग्रेस डेमोक्रेटिक फ्रंट को 20 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था जबकि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट को 19 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। इनमें अध्यक्ष जो एम जी पी के सदस्य हैं, शामिल नहीं हैं। अध्यक्ष ने राज्यपाल को सूचित किया था यदि आवश्यक हुआ तो वे त्यागपत्र दे देंगे और एम०जी० पी० के साधारण सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। इस प्रकार दोनों पार्टियों की 40 सदस्यों के सदन में संख्या 20–20 थी।

राजनीतिक गतिरोध के परिणाम स्वरूप राज्यपाल ने महसूस किया कि दोनों में से कोई भी पार्टी न तो स्थाई सरकार बना सकती है और न ही स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। राज्यपाल ने यह भी उल्लेख किया था कि किस प्रकार विधान सभा सदस्यों की विश्वसनीयता और वफादारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता तथा विधान सभा सदस्यों को दल बदलने के लिए अत्याधिक दबाव डाला जा रहा है।

राज्यपाल ने आगे यह भी कहा था कि राज्य में राजनीतिक स्थिति अत्याधिक जटिल होती जा रही है, क्योंकि गोआन पीपल पार्टी के 7 सदस्य, जिनमें से 4 सी० डी० एफ० तथा 3 पी० डी० एफ० के साथ हैं, दल बदल विरोधी कानून के अन्तर्गत अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। इसके साथ-साथ एम जी पी के दो सदस्यों के विरुद्ध भी, जिन्होंने सी एफ डी को समर्थन दिया है, दल बदल विरोधी कानून के अधीन कार्रवाई की जा सकती है। सी एफ डी० ने अध्यक्ष को हटाने का अभियान भी शुरू कर दिया था ताकि दल बदल विरोधी कानून के अन्तर्गत कार्रवाई न की जा सके।

राज्यपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि साफ-सुथरा प्रशासन देने के लिए कोई भी पार्टी स्थाई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तदनुसार राज्यपाल ने सिफारिश की थी कि राज्य विधान सभा को भंग किया जाए और जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।

संघ सरकार ने राज्यपाल की रिपोर्ट और गोवा की स्थिति पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तथापि यह महसूस किया गया कि विधान सभा को भंग न किया जाए बल्कि उसे निलंबित रखा जाए। तदनुसार राष्ट्रपति को सलाह दी गई। संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 14 दिसम्बर, 1990 को उद्घोषणा जारी की गई और विधान सभा को निलंबित कर दिया गया।

महोदय, मेरे द्वारा अभी स्पष्ट की गई परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए मैं सिफारिश करता हूं कि गोवा राज्य के संबंध में यह माननीय सदन संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 14 दिसम्बर, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करे।

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Resolution moved.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): I thank you for calling me first, feeing the only Member from the State of Goa. Since the last general elections in Goa, the composition of Goa Assembly bad a peculiar position for the first t[4]me in the democratic history of Goa. In that out of 40 seats, elections were held to 38 Assembly constituencies. The MGF bagged 18 seat$_s$ and th$_e$ Congress(I) also bagged 18 seats with one independent candidate supporting each side. Two seats were countermanded

as there was some dispute. Subsequently when results for these two seats were declared, it was again a peculiar position for putting any decision in that. The Congress (I) had 20 "" out of 40 seats. With the support of one Independent the Congress(I) had formed a Government. But subsequently on 26th of March, the PDF coalition Government with the help of seven GPP MLAs, who had defected from the Congress(I), formed a Government with the MGP. On 21st November, i. e. last year, this coalition came in crisis and the MGP withdrew the support to the GPP on 10th of December. The Chief Minister did not face the House and the Governor, rightly or wrongly, sub-mittted a report to the Centre. The subsequent grouping and regrouping brought the. tally to 20 each of PDF and the newly formed CDF i. e. Congress Democratic Front. On 12th of December the Speaker broke the stalemate by disqualifying the MGP MLAs on ground of defection. The caretaker CM vas disqualified by the Members elected by the House to consider defection of the then Speaker. This brought the tally with 50 MGP MALs and 17 CDF MLAs. But in spite of this ratio, it surprising how the Centre imposed President's Rule. I could have understood the Centre corsidering on the 12th of December, before the Speaker's decision, when there was a stalemate of 20 each on either side. It was shock'ng and surprising with the office of the Governor dragging itself in politics by stating that he will consider the High Court verdict, when the court had no jurisdiction to interfere as per the Tenth Scnedule of the Anti-Defection Act. The Governor should have consulted the Advocate-General or the Law Department before making any ouMie announcement. This tantamounts to showing disrespect to the Legislature. The Governor's b' ag anri interference with the Legislature, which is not the domain of the office of the Governor can be understood from the report he submitted to the President recommending the dissolution of the State Assembly. This gives a clear indication that the Governor wasin a hurry to take salute on the Goa Liberation Day on the ISth of December, when it is the actual practice that the Chief Minister of that States takes the salute without having any regard to the wishes of the people of Goa. 1 compliment the Home Minister for not dissolving the Assembly in spite of the Governor';; report recommending for dissolution. They have an intention of installing a Government and I compliment him for that. He has also made a statement in the Lok Sabha that a popular Government will be installed when the situation is conducive.

To add insuit to injury, the Governor had appointed a retired IAS officer as Advisor to make a mockery of this democratic institution. This retired IAS officer was installed in the chair of the Chief Minister and was shifted to the official residence of the Chief Minister. I already had a discussion in this matter with the hon. Home Minister and I feel that he would rect' fy the situation. I am happy to note that the Home Ministry is very much vr'lling to install a new and popular Government. "Recently we had reports that there is realignment of groups in Goa. £ am told that the CDF party has a majority. I would like to know from the Home Minister, what is the present report? (Interruptions)... You have mentioned about the report submitted by the Governor when the Assembly was suspended hut I am told that with the regrouping of MLAs the CDF Carty has a majority. May I know from the Minister whether he would consider to install this Government at the earl'ests? The Governor of Goa has been transferred. That is a positive thing. May I know from the Home Mi nister bv when he is going to wooint a full-PedgeH Governor? Once again I comoliment the Home Minister for taking a bol* decision and announcing in the Lok Sabha

[Shri John. F. Fermandes]

that a popular Government will he installed when the sitution is conducive. I hope he will make that announcement in this House also and the President's rule is revoked in Goa at the earliest.

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, गोवा में राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा हुई उस संबंध में गृह मंत्री जी संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन गोवा राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि के अनुमोदन पर मोहर लगाने के लिए यहां पर विधेयक लाये हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं बहुत नम्रता के साथ कि जनतंत्र की जो हमारी प्रणाली है और जो हमारा संविधान है वह संविधान इन बातों पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से जनतंत्र की प्रणाली को सुरक्षित रखते हैं। जहां कहीं भी राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं वहां संविधान के खिलाफ कार्य करते हैं। क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम जनतंत्र प्रणाली की चलाने के लिए जनता की मर्जी के अनुसार सरकार की स्थापना करेंगे। आज देश के एक-तिहाई हिस्से में राष्ट्रपति शासन है, जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हैं, पंजाब में राष्ट्रपति शासन हैं असम में राष्ट्रपति शासन हैं पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन है। गोवा में राष्ट्रपति शासन है। यह भी मैं कहना चाहता हूं बड़े अदब के साथ कि जब से नई सरकार आई, मेरा मतलब चन्द्रशेखर की सरकार से है, तब से राष्ट्रपति शासन की प्रणाली कुछ आगे बढ़ी है। जिन प्रांतों में भी जनतांत्रिक ढंग से सरकारें चल रही हैं वहां पर किसी न किसी रूप में उसको समाप्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जा रहा है। गोवा में जो विगत चुनाव हुआ था उसमें 18 सीटें कांग्रेस को मिली थीं और 22 सीटें कांग्रेस विरोधी दलों को मिली थीं। कांग्रेस ने उनमें तोड़-फोड़ करके अपनी सरकार बना ली और जब सरकार टूटी तो इस तरह से चाल चली कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। गोवा प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। गोवा के समुद्री तट हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और समृद्धि की खान बन सकते हैं। लेकिन जहां कहीं भी राष्ट्रपति शासन होता है वहां पर्यटक भी जाने में झिझकते हैं। इसलिए मैं बड़े आदर के साथ गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अनुमोदन के लिए यह हमारे बीच में लाये हैं लेकिन अपने दिल से इस बात को हटा दीजिए कि राष्ट्रपति शासन से जनतांत्रिक प्रणाली चल सकती है। ठीक है वहां की राज्यपाल की रिपोर्ट आ गई है। आप भी जानते हैं, पार्लियामेंट के सभी मेम्बर जानते हैं कि राज्यपाल किस तरह से रिपोर्ट भेजते हैं। केन्द्रीय सरकार की मंशा के अनुसार ही रिपोर्टें आती हैं, लेकिन जैसा कि हमारे मित्र वहां के माननीय सदस्य ने कहा, उसकी निगरानी तो आप ही क० सकते हैं। आपने एक आई.ए.एस० अधिकारी को सलाहकार के रूप में वहां नियुक्त किया और वह चला गया मुख्य मंत्री के निवास में। आप सोचिये कि ऐसी स्थिति में मुख्य मंत्री की गरिमा क्या रहेगी? मुख्य मंत्री इलेक्टेड होता है और वही सुप्रीम बाडी है, उसकी जगह आपका सलाहकार चला गया। अभी वहां पर कोई राज्यपाल भी या नहीं, मैं नहीं जानता, क्योंकि वहां के राज्यपाल को आपने कर्नाटक भेज दिया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, कि गोवा में राष्ट्रपति शासन है। आपने वहां गवर्नर का सलाहकार नियुक्त किया, वह मुख्य मंत्री के निवास में जाकर मुख्य मंत्री बन गया। वहां पर राज्यपाल नहीं है। ऐसी छिछालेदार को स्थिति सरकार के द्वारा कहीं भी पैदा नहीं की जानी चाहिये, यह बात मैं सरकार से निश्चित रूप से कहना चाहता हूं। हमारे गृह मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं, उनका व्यक्तिगत रूप से मैं बड़ा आदर करता हूं। वे बड़े डेमोक्रेटिक रूप के आदमी है। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि गोवा में राष्ट्रपति शासन की मोहर लगाने हेतु जब वे इस आवेदन को हमारे सामने लाये हैं तो इसके साथ साथ वे यह भी घोषणा करें कि और कहीं भी राष्ट्रपति शासन अब लागू नहीं

किया जायेगा और जहां भी राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है उसकी अवधि नहीं बढ़ाई जायेगी, वहां चुनाव कराये जायेंगे । इन शब्दों के साथ जो धारा 356 के अनुसार हमारे सामने यह प्रस्ताव आया है उसका समर्थन मैं आंशिक रूप से कर रहा हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA); Smt. Margaret Alva is not there. Mr. Nai ayanasamy

SHRI DINESH GOSWAMI (Assam); Mr Narayanasamy can take as much time as possible.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry); I know why you are saying so.

SHRI S. B. CHAVAN: (Maharashtra): He does not want the Assam matter today.

SHRI V. NARAYANASAMY: i support the resolution moved by the hon. Home Minister. From January 1990, the situation in Goa was all right. In the general elections for Goa in January 1990, the Congress had 20 MLA seats; 18 were held by the MGP and two by independents. One independent joined the Congress party and a majority Government was formed under the Chiefministership of Pratap Singh Rane. What happened was after four months, the ministry was disturbed. The ministry was disturbed by not less a person than a Cabinet Minister in the National Front Government. It was a known fact that Shri George Fernandes, the then Railway Minister, went to Goa and used his influence with the MLAs and money bags were sent to Goa.

AN HON. MEMBER: Wrong, wrong.

SHRI V. NARAYANASAMY: Money bags were sent to Goa to topple the Pratap Singh Rane Government by Mr. George Fernandes, the then Railway Minister. Six MLAs and the Speaker of the Legislative Assembly, Dr. Barbo? a, defected from the Con-gress party and they called themselves the Goan People's Party. And there was a marriage of convenience between the MGP and the group which was headed by Dr. Barbosa. When that tussle was going on, for short spell of time, President's rule was imposed, for a period of six days. In the meanwhile, an interna Chief Minister was installed. Thereafter, with an understanding that Dr. Barbosa would be made the Chief Minister of the State on the assurance given by the then Railway Minister who was interested in toppling the Congress Gov. ernment. Then, Dr. Barbosa was elected as the Chief Minister of the State. Sir, Mr. George Fernandes did not stop with Goa alone. He went to Manipur. There, he engineered defections. The Congress (I) Government was disturbed there. Then he went to Meghalaya. In Meghalaya, the Congress(I) Government was toppled with the help of heavy money bags which he carried along with him in his helicopter. Then he touched Nagaland also. He entered Nagaland one day. Next day, the Government was in trouble. They selected only the Congress Governments and the Congress Governments were disturbed by using the influence of the National Front Government at the Centre and George Fernandes could succeed by using the mony power and the power they held at Delhi, intimately, what happened? The Governments which were disturbed by the National Front Government, now they are in doldrums. Those people who defected from the Congress Party, now they are realising what they have committed was wrong and for a short honeymoon, they went to another political party and now they are on their way to the Congress party. It is a shame on the part of the then Ministers of the National Front Government; who took steps to destabilise certain Governments. It is very patent in the case of Goa. Sir, with all authority, I can say before this riouse, at the time when Goa Government... *(Interruptions).* Sir, I have plenty of material t > speak about it. I may be given some more time because no other speaker is speaking from our side.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): More speakers are there from other parties also. Please be brief.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, our party has 53 minutes' time. Therefore, would like to take a little more time.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): What I am saying is, try to be brief.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I do not want to enter into dialogue and I would speak. What happened in Goa? At the time when the Government was to be toppled, Mr. George Fernandes approached the Congress MPs and told them that they would be made Ministers in the Central Cabinet. He gave this assurance to the MPs of the Congress party. *(Interruptions).* If he wants to confront me, I am prepared. And the Congress (I) Members of Parliament turned down the proposal. The reason was that from the Christian community, there was no one except himself in the Cabinet. Therefore, he wants them to be taken in the Cabinet. That was the assurance which he gave to them. But unfortunately the Congress (I) Members of Parliament did not yield to his request. This was a sorry state of affairs, I would say. Mr. George Fernandes was responsible for toppling four Congress (I) ruled State Governments. (Interruptions).

SHRI DINESH GOSWAMI: Sir, I am on a point of order. At least the name of a Member who is a Member of the other House, should not be taken. He may refer generelly.

SHRi. V. NARAYANASAMY: Sir, I am referring to him in his capacity as a Central Minister. I am not referring to him as a Member of Parliament. He was a Minister. He was responsible... (Interruptions).

SHRl DINESH GOSWAMI; Let me formulate my point of order. Obviously, this House can refer to previous Central Minister if he acts as a Central Minister. But a person even if he is a Central Minister does not act in hig official capacity as a Centrel Minister and personal allegations are made against him. That should not come in the record because that gen- ~ tleman is not in a position to defend himself and therefore, I will submit that the names should not come.

SHRI M. M. JACOB (Kerala): Sir, it was difficult for us to And out the official capacity of a Central Minister at that time. *(Interruptions).*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): I shall only request the Members to avoid such points.

SHRI V. NARAYANASAMY; Sir, it is a hard fact which they cannot swallow. That is the whole trouble.

SHRI DINESH GOSWAMI; I certainly deny this but I took the plea because it will be a very unhealthy convention if we refer to persons who are not in a position to defend themselves in the House, particularly, an hon. Member of the other House.

SHRI V. NARAYANASAMY: Then, I can refer to him as the former Railway Minister in the V. P. Singh's Government.

THE VICE-CHAIRMAN DR. NAGEN SAIKIA); Yes, you can refer to him in that way. But George Fernandes is a Member of the other House.

SHRI V. NARAYANASAMY; I am not referring to him.

SHRI N. K. P. SALVE (Maharashtra): I am sure he must have travelled on Government account to all these places. And if he has travelled on Government account, it is not a private visit.

SHRI V. NARAYANASAMY; Sir, as has been rightly observed by one of the hon. Members, he used the Raj Bhavan as the National Front headquarters in those days. He called the MLAs and gave them all kinds of

assurances. And as I said, money played a major role in toppling the Congress (I) Governments. That is why I am pained. Moreover, when these 7 persons had come out of the party and joined with the Maharashtrawadi Gomantak Party, they formed the Government. What happened in the Government? There were serious differences of opinion in the Council of Ministers, especially between the Deputy Chief Minister and the Chief Minister. There were two important and vital issues.

One is whether Konkani should be the official language or Marathi should be the official language. The Deputy Chief Minister wh$_0$ belonged to Maharashtrawadi Gomantak Party wanted that Marathi should be the official language of Goa. The Chief Minister$_i$ Dr. Barbosa, was very particular that Konkani should be the official language of the State. There was a difference of opinion between the two political parties and in the appointment of Chairmen of State undertakings the differences arose because th$_e$ Deputy Chief Minister suggested some names and the Chief Minister suggested some names on which there was no agreement between them and then they started working against the interests of the State. What is worrying us is right from March to December first week there was no Government functioning. The only thing that was going on was horse-trading. The Deputy Chief Minister tried to woo back some of the MILAS and even the Ministers in the Barbosa Government and Dr. Barbosa tried to get more MLAs, Congress (I) MLAs, with him. Fortunately, Congress (I) MLAs could not be taken to his side by Dr. Barbosa because they were committed and they did not yield. Ultimately what happened was when the Maharashtrawadi Gomantak Party withdrew its support saying that it had ideological differences with the Chief Minister, three Ministers including the Deputy Chief Minister went to the Governor and submitted a memorandum, They also said that they were withdrawing their support to Dr. Barbosa Government. The next day they did not turn up. They sent

a letter saying that they were withdrawing their support. But Dr. Barbosa was very confident that he would prove his majority on the floor of the House. Ultimately what happened? Some of the persons who were supporting Dr. Barbosa als$_0$ defected. There was horse-trading and the Legislative Assembly Members were kept in confinement and they could not go out freely. This was happening. Especially the Deputy Chief Minister who was making a bid to form the Government, was keeping the MLAs under confinement with him to get a majority. Ultimately there was a tie. Twenty persons belonged to harashtrawadi Gomantak Party and the other 20 remained out-Bide. Therefore, the Governor sent so many reports to the Centre. He came to the conclusion that there was no political party which could form a stable Government and therefore, he submitted a report to the Home Ministry and also to the President for necessary action. It is a right decision by the Central Government to impose President's rule and keep the Assembly under suspended animation So, some time has elapsed. But none of the political parties is able to form a Government so far. In this political crisis prevailing in Goa which is a very g, ood tourist spot and which is getting a lot of revenue to the State, the entire administration is in peril. The Government has imposed President's rule and kept the Assembly in suspended animation. An Adviser has been appointed. The Adviser did not take into consideration the suggestions given by the Members of the Legislative As-sembly. Therefore, I would request the Home Minister to Constitute an advisory council till such time that a decision is taken on the formation of Government or dissolution of the Assembly. The advisory council should comprise MLAs for the purpose of advising the Government for normal administration of the State. Keeping the Assembly jn suspended

[Shri V. Narayanasamy]

animation for a long time will not serve any purpose. Instead, it will lead to horse-trading. Now we are seeing the game everyday. One group comes and claims it has the majority to form a Government. Another group comes and says it has the majority and it will form a Government. We don't know which MLA is in which group. If this situation continues, then the political morality will go down. Keeping the Assembly in suspended animation will lead to a lot of speculation in the State and the very institution of Legislature will be brought down. Therefore, I would request the Home Minister to ponder over this and find out whether there is a possibility of a Government being formed by a majority party failing which the Central Government should take a decision for a better administration in the State. This apart, I would like to say how the Speakers are behaving in the States. The Speakers in the State Legislatures.

especially now under the anti-defection law, are taking different decisions under the Tenth Schedule to the Constitution. Unified procedures and rules and regulations are not being followed. Whenever any application is filed for disqualifying a Member of the Legislative Assembly, decisions are taken without giving notice to the Member or Members concerned. This has happened in Goa also. In my own State, Pondicherry, you know what happened. Notices were issued to two MLAs for disqualification and without giving them opportunity to show cause the two legislators were disqualified. Thereafter, the order was repealed by the Speaker. The Speaker has no power to repeal his own order. But it was done by him. Therefore, it is

time that the Tenth Schedule to the Constitution was reframed so that the power should not vest fully with the Speaker and a uniform procedure should be followed by all the Speakers in the country, *{interruptions)* Let me tell you, even the Chief Minister, Dr. Barbosa, was disqualified by the Speaker. The Chief Minister and two other MLAs were disqualified by the Speaker. I, therefore, submit that the Tenth Schedule to'the Constitution should be suitably reframed. The Home Minister is **sitting here. I** would ^ request him, there should be a review of the powers conferred on the Speakers. There should be a review of the provision which contains enormous powers and which confers enormous powers on the Speaker That should be studied by the Home Ministry and the Law Ministry and they should come out with specific proposals.

In this connection, I have one pro-posal to make for the purpose of sharing the powers of the Speaker in deciding disqualification. Under the provisions of the Tenth. Schedule, whenever any application is filed for the disqualification of any Member, the Speaker should decide the matter.. Apart from the matter being referred to the Privileges Committee, the Leader of the House and the Leader of the Opposition also should have a say in the matter. This is my proposal. They also should have a say in the matter so that justice can be rendered to the parties concerned. Therefore, j would like to say that the honourable Home Minister should respond to the queries that I have raised and also to this proposal of mine.

How long are you going to keep the Assembly in suspended animation? The people of Goa very much want a popular Government in the State. What decision are you going to take? If you keep the Assembly in suspended animation for a long period, that will not be good for the State because that would give scope for horse-trading and would vitiate the political system in the State. Therefore, a decision should be taken soon about keeping the Assembly in suspended animation. Moreover, I welcome the announcement made by the honourable Minister regarding imposition of the President's Rule in the State because I of the peculiar circumstances under

which th© MLAs have been divided in the State, very much equally, into twenty on one side and twenty on the other. Therefore, I support the Resolution moved by the honourable Minister.

With these words, I conclude, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA); Before I call the next speaker, I would like to inform the honourable Members that Mr. Bhakata Charan Das, Minister of State in the Ministry of Railways will make a statement at 6-00 P. M. today regarding the collision between a local EMU train and a goods train on the Eastern Railway on 6-1-91.

This point was raised in the House earlier.

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Sir, I will be very brief.

Sir, I oppose the imposition of President's Rule in Goa and also keep, ing the Assembly in suspended animation.

Sir, we have all along been opposing application of article 356 of the Constitution and the curtailment of the powers of the Legislature, and there is no doubt about it. I would like to say that if you keep the Assembly in a state of suspended. animation, it gives enough scope for horse-trading. In fact, what has happened in Goa is that it has already started taking place there. Without going into the details of the matter. I would like to tell the honourable Minister that the Assembly should immediately be dissolved and elections should be arranged so that things are settled there. Thank you. Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA); What is it chat you wanted to say, Mr. Kulabidhu Singh?

SHRI W. KULABIDHU SINGH (Manipur'! Sir, what about the allegation made against Mr. George Fernandes who is hot a Member of this House?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): That point i_s over. That point has already been discussed. It should not be raised now.

SHRI W. KULABIDHU SINGH: Sir, they were charging Mr. George Fernandes with encouraging defections. The fact is that Mr. George Fernandes visited Manipur in the third week of February and the defections in Manipur took place in the last week of July. A clear six month's gap was there. So, such misleading information should be discouraged.

THE VICE-CHAIRMAN DR. NAGEN SAIKIA); All right. Now, Basant Kumar Das.

श्री बसन्त कुमार दास (उड़ीसा) : आनरेबल वाईस चेयरमैन सर, हमारे गृह मंत्री जो गोआ में राष्ट्रपति शासन का मोशन लाये हैं, उसका समर्थन करता हुआ मैं यह बोलना चाहूंगा कि गोआ में जब सरकार बनी थी आठ नौ महीने पहले जैसा कि मान्यवर गोआ के सदस्य, अभी बोले, उस वक्त से ही ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि एक स्थाई और स्थिर सरकार नहीं बन सकती थी। फिर भी एक स्थिर सरकार दो पार्टियों को लेकर बन गई। जिस दिन से सरकार बनी, उसी दिन से छोटे-मोटे झगड़े दोनों पार्टियों के बीच होते रहे है । अन्त में यह छोटे-मोटे झगड़े स्पष्ट रूप से जनमानस के सामने आ गये जब 19 नवम्बर को वह शासन करते हुये एक गुट ने रेजोल्यूशन करके लिख कर गवर्नर साहब को दे दिये कि वह सरकार से हट रहे हैं और उसी दिन ही ऐसी परिस्थिति शुरू हो गई थी कि गोवा में कोई वैकल्पिक व्यवस्था की चिंता करनी चाहिये थी । लेकिन सराहनीय बात यह है कि, सरकार प्रशंसा का भाजन इसलिये है जब 29 तारीख को यह सरकार गिर गई थी फिर भी गणतंत्र का मूल्यबोध उसको सम्मा:

[श्री बसन्त कुमार दास]

देने के लिये सरकार ने 14 तारीख तक जो विभिन्न प्रक्रिया चलती रही गोवा में उसको देखते हुये 14 तारीख तक, जब 14 तारीख को गवर्नर का फाइनल रिपोर्ट आ गया कि इतनी देर इंतजार करने के बाद में भी जब सरकार नहीं बन पाती है तो और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, न चाहते हुए भी दुख के साथ गोवा में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और मान्यवर गृह मंत्री केन्द्र सरकार का गवर्नर का जो रेकमंडेशन था हाउस को भी डिजाल्व करने के लिए उसको भी विचार में न लेकर फिर भी गणतंत्र प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, सम्मान देने के लिए जो कदम उठाया है। इसलिए सरकार के यह कार्यक्रम का मैं स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं मान्यवर, गृह मंत्री जी से कि वह देखें व्यवस्था ऐसे करें जो जल्दी ही अगर सरकार नहीं बन पाती है, यह डेमोक्रेटिक इस्टीट्यूशन को, उसकी वैल्यू को बचाए रखने के लिए ज्यादा देर यह सस्पैंडेड एनीमेशन में असेंबली को न रखते हुए जल्दी निर्वाचन की व्यवस्था, इलेक्शन की व्यवस्था करें और एक प्रतिष्ठित सरकार की स्थापना हो जाए इस दिशा में वह कदम बढ़ाए और इसी के साथ, हम धन्यवाद के साथ, इस बिल को सपोर्ट करते हुए इजाजत चाहते हैं ।

श्री संजय प्रिय गोतम (उत्तर प्रदेश) मान्यवर उपसभाध्यक्ष महोदया गोवा एक छोटा सा सूबा है। सदस्यों की संख्या कुल 40 है 11 महीने के अन्दर स्थिति देखिए, विडंबना देखिए कि सरकार चार बार टूटी बिगड़ी और बनी। मुख्य मंत्री बदले और बदलने के प्रस्ताव आए। स्थिति क्या थी ? चुनाव के तुरन्त बाद की स्थिति यह थी कि कुल मिलाकर कांग्रेस और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी दो राजनीतिक दल थे। 20 सीटें कांग्रेस को मिलीं, 18 एम जी पी को मिलीं, एक-एक निर्दलीय आए। दोनों में से एक कांग्रेस के साथ, एक एम जी पी के साथ मिल कर 21 और 19 हो गए और चुनाचे दो के बहुमत से कांग्रेस की सरकार मि० राणे के नेतृत्व में बना दी गई। बड़ी मुश्किल से दो महीने सरकार चली। हमारे लोग तो आरोप-प्रत्यारोप लगाने की आदत में कुछ डूब गए हैं। मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि सरकार कैसे टूटी, लेकिन कांग्रेस के 6 सदस्य और एक स्पीकर जो कांग्रेस पार्टी में आए थे, लेकिन स्पीकर बन जाने के बाद उनका दर्जा इंडीपेंडेंट का हो गया, 7 आदमी डिफैक्ट कर गए और उन्होंने गोवन्स पीपुल्ज पार्टी के नाम पर एक अलग दल बना लिया और फिर उन्होंने गवर्नर को एप्रोच किया कि एम०जी पी हमको सपोर्ट करना चाहती है। चुनाचे हमें सरकार बनाने का मौका दिया जाए। मि० चर्चिल के नेतृत्व में 15 दिन ही हो पाए थे कि पि० चर्चिल ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि हम डा० बारबोसा को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। चुनाचे डा० बारबोसा चीफ मिनिस्टर हो गए। इसी दौरान प्रक्रिया यह हुई कि एम०जी पी० के भी आदमी टूट गए और जो कांग्रेस में से 7 टूट करके आए थे गोवन्स पीपुल्ज पार्टी वह भी टूट गई और तीन एक तरफ हो गए, चार एक तरफ हो गए। अब यह टूटने की, बनने-बिगड़ने की प्रक्रिया ऐसी चली कि "इतदाए इश्क में रोता है क्या, आगे-आगे देखिए होता है क्या"। वह 3 और 4 उसमें से बन गए। इस दौरान एम०जी पी ने डा० बारबोसा से अपना समर्थन वापिस ले लिया। अब लेटेस्ट स्थिति क्या है ? कांग्रेस के साथ 13 रह गए, 7 निकल गए उन्हें 4 का समर्थन गोअंस पीपुल्स पार्टी में से हुआ 13 और 4, 17 हुए। एक उनके साथ इंडपेंडेंट 18 और 2 एम जी०पी के जो डिफेक्ट किए थे। इस तरह से कुल 20 है कांग्रेस गठबंधन के साथ। लेकिन वे 2 जो एम०पी०जी० वाले हैं, उनका भी भविष्य अनिश्चित हो गया है। कोर्ट में उनका केस पेंडिंग है, वे स्टे लेकर आए हैं। डा० बारबोसा का भी केस कोर्ट में पेंडिंग है। उधर जो एम०जी०पी० गठबंधन है, उसकी स्थिति क्या है ? 16 एम०जी०पी० के, 1 इंडेपेंडेंट 17 और 3 गोअंस पीपुल्स पार्टी के। उनके भी 20 हैं। दोनों तरफ बीस-बीस हैं। बहुमत किसी का नहीं है। ऐसी स्थिति में एसें-

बली को. सस्पेंड रखने का मतलब है, हार्स ट्रेडिंग के लिए मौका देना, दल-बदल के लिए मौका देना, कई बार दलों को तोड़ने का मौका देना ।

मान्यवर, सन् 1967 में देश के विभिन्न राज्यों में व्यापक पैमाने पर दल-बदल हुआ था और उस दल-बदल के बाद इस देश में विभिन्न दलों की मिल-जुलकर सरकारें बननें का सिलसिला शुरू हुआ । लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि इन मिली-जुली सरकारों का समय बड़ा अनिश्चित रहा है । इन्होंने, शायद ही अपना टर्म पूरा किया । ये आज बने ही होता, लेकिन देश की राजनीति, जनता और प्रशासन पर इसका क्या असर पड़ा है ? इससे राजनीतिक प्रक्रिया बड़ी कमजोर हुई है । जो राजनीतिक पार्टियां थीं, मिली-जुली सरकारें जो बनीं, उनका वजन पब्लिक की निगाहों में कम हुआ । वह कुछ सख्ती से अमल कर पाएंगी, इसका भय जनता के दिमाग से निकला और ऐसी सरकारों पर ब्यूरोक्रेट्स का दबाव पड़ा । इससे यहां डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को ठेस पहुंची । मान्यवर, चूंकि यह प्रक्रिया बराबर जारी रही और हमारी वर्तमान सरकार भी उसी प्रक्रिया को जारी रखना चाहती है क्योंकि यह भी दल तोड़कर बनी है । यह भी कोइलीशन गवर्नमेंट है और इसका भी भविष्य अनिश्चित है । इससे बड़ा भारी नुकसान हो रहा है । इसलिए इस प्रोसेस को जारी न रखा जाए । अब इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है कि गोवा के अंदर विधान सभा को तुरन्त भंग कर चुनाव कराए जाएं । इसलिए मैं आपके इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री मोहम्मद अलोलुर रहमान (आंध्र प्रदेश) : जनाब वाइस चैयरमैन साहब, गोवा में जो प्रेसीडेंट रूल लाया गया है और वहां की एसेंबली को मुअत्तिल किया गया है, उसकी मैं मजम्मत करता हूं ।

यह आया राम, गया राम की रोशन मिसाल है । जहां तक आर्टिकल 356 का सवाल है, हमारे दस्तूर बनाने वालों की यह मंशा थी कि इंतहाई मोहतात में इसको इस्तेमाल किया जाए और कभी भी गलत तरीके से आर्टिकल 356 का इस्तेमाल न किया जाए । मगर पिछले 40 सालों में हमने देखा है कि कांग्रेसी हुकूमत और उसकी हमनवा हुकूमत हमेशा इस बात की कोशिश करती रहीं कि आर्टिकल 356 से खेला जाए कर हर वक्त आर्टिकल 356 से खेला गया । चुनांचे, गोवा में भी इसका इस्तेमाल किया गया । इस वक्त जो गोवा की सूरते-हाल है, उस सूरते-हाल की जो असल जम्मेदारी है, वह असल जिम्मेदारी वहां की कांग्रेस पार्टी और वहां की एम जी पी है । एम जी पी के जो लीडर हैं हमारे रमाकांत खेलप, जो कि वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं , उन्होंने कांग्रेस के लालच में आकर चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाइश में यह गैम खेला और अपने 10 लोगों के साथ, जो वहां की फ्रंट गवर्नमेंट थी, उससे उन्होंने सपोर्ट वापिस ले लिया । मगर फिर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें धोखा दिया और उन्हें चीफ मिनिस्टर बनने से रोका और आज सूरतेहाल इस किस्म की है कि कोई भी पार्टी इस मोअक्कफ में नहीं है कि वहां पर हुकूमत बना सके । मगर जैसा कि वहां के गवर्नर साहब ने सिफारिश की थी कि सदर-राज को कायम किया जाए और साथ

[श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान]

ही साथ असेम्बली को तहलील किया जाए, मगर पता नहीं कि मरकजी हुकूमत ने किस लिहाज से वहां की असेम्बली को तहलील करने के बजाए, उसको मुअत्तिल रखा है । में समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के असर में आकर यहां की मरकजी हुकूमत ने वहां की असेम्बली को मुअत्तिल रखा है ताकि आने वाले दिनों में हार्स-ट्रेडिंग हो और फिर घोड़ों का बाजार गर्म हो जाए । चुनांचे वहां के गवर्नर साहब ने भी एक इन्टरव्यू दिया है प्रेस में और उन्होंने कहा है कि असेम्बली को मुअत्तिल इसी लिए रखा गया है ताकि फिर दोबारा रीग्रुपिंग हो । इससे साफ जाहिर होता है कि वहां पर घोड़ों की रेस होने वाली है, काफी पैसा खर्च होने वाला है ।

लिहाजा जरूरत इस बात की है कि फौरी असेम्बली को डिजॉल्व किया जाए और जल्द से जल्द नए इलेक्शन करवाए जाएं ताकि वहां के आवाम की अपनी मर्जी की हुकूमत गोवा में कायम हो सके । यह मेरा हुकूमते-हिन्द से मुतालबा है ।

[شری محمد خلیل الرحمان

(آندھرا پردیش) : جناب وائس چیئرمین صاحب گوا میں جو پریسیڈنٹ رول لایا گیا ہے اور وہاں کی اسمبلی کو معطل کیا گیا ہے - اسکی میں مذمت کرتا ہوں -

یہ آیا رام گیا رام کی روشن مثال ہے- جہاں تک آرٹیکل ۳۵۶ کا سوال ہے ہمارے دستور بنانے والوں کی یہ منشا تھی کہ انتہائی محتاط میں اسکو استعمال کیا جائے - اور کبھی بھی غلط طریقے سے آرٹیکل ۳۵۶ کا استعمال نہ کیا جائے - مگر پچھلے ۴۰ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کانگریسی حکومت اور اسکی ہم نوا حکومت ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتی رہیں کہ آرٹیکل ۳۵۶ سے کھیلا جائے اور ہر وقت آرٹیکل ۳۵۶ سے کھیلا کیا - چنانچہ گوا میں بھی اسکا استعمال [کیا گیا - اس وقت جو گوا کی صورتحال ہے - اس صورتحال جو کی اصل ذمہ داری ہے- وہ اصل ذمہ داری وہاں کی کانگریس پارٹی اور وہاں کی ایم - جی - پی- ہے - ایم - جی - پی - کے جو لیڈر ہیں ہمارے رماکانت کھیلپ - جوکہ وہاں کے ڈپٹی چیف منسٹر بھی رہے ہیں - انہوں نے کانگریس کے لالچ میں آکر چیف منسٹر بننے کی خواہش میں یہ گیم کھیلا اور اپنے ۱۰ لوگوں کے ساتھ جو وہاں کی فرنٹ گورنمنٹ تھی اس سے انہوں نے سپورٹ واپس لے لیا - مگر پھر کانگریس پارٹی نے انہیں دھوکا دیا اور انہیں چیف منسٹر بننے سے روکا اور آج صورتحال اس قسم کی ہے کہ کوئی بھی پارٹی اس موقف میں نہیں ہے کہ وہاں پر حکومت

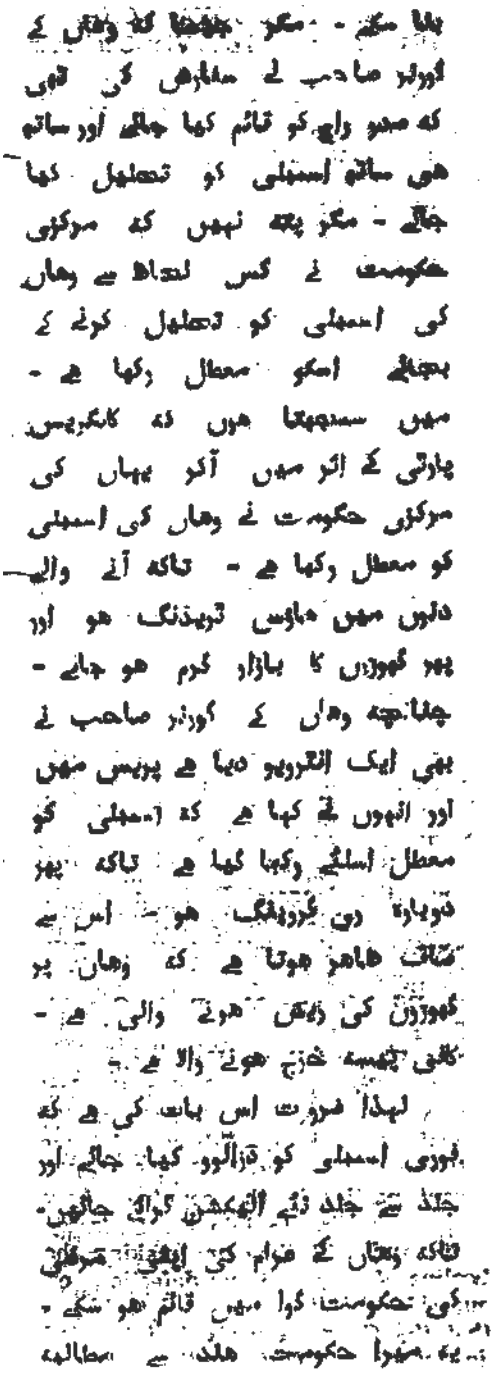

SBBI ^_i.QOPA^SAMY_r (Tamjl Nftdu^v ; H|LM y|ce-Chateian, many., *y&Bfy* "back, the fate of Gpa *Jfas* to ee_K deefeifesd; acooy&ng to w^iins aKd faa-^ ciesl'of iuc rulers sitting fin Listion! it,.^

is very unfortuntt* today that the fate og «Ha* <3o» is to ba decided by *Atofr* Delhi durb»,.. interruptions). 1 can; not gad -fcwtft with my friend, ftfe. Subodh .KMft Sahay, because «« name it«ejf say_s fee is always for 'sahay'that means help; but "he find* himself helpless as long as article 35ft stands there like a Damocle's sword t hanging. Whichever party sits in *h? -saddle in Delhi, they are tempted to use this article which cuts at the very; root of the spirit of federalism in the' country....

SHRI V. NARAYANASAMY:.. .including National Front.

SHRI V, GOPALSAMY: You can make your own interpretation.

SHRI V. NARAYANASAMY: You say that also,

SHRI V. GOPALSAMY: Unless you rub me on the wrong side, you may keep quiet.

This is to be condemned. This culture of horse-trading, that is, *Aya*-Rom-Goyo-Rom, this murky and dirty business, should-b© condemned by all sections. In politics, we may have high-diffierences of opinion; but we 'should stick to our conviction, and to our prin-cipjfes^-Whether .we win. or we are de-feated^we.should sit under the -same ^ umbrella, .".Bu£ the leaders of the! parties, the legislators are purchased ag vegetables are purchased from a vegetable .markeyU,Ji50ien_I_r^.yJt isio be condemned, "i ask, who 4 responsible for nurturing this nasty business, and I rajsje my; jessingBnger" agaih^ the Congress-I party in this country for nurturing thiawaty, business, since indeperidenot.'Whetiever they find'^ Opposition Party 'occupying the Chair, they won't sit silent. They will create trouble and they will spread some canard. They ,w#Vipread all kinds- cf i nasty stories and hte_v. _will tr/to-pur-i cfiase ML As. This is the trick they : have always been employing.

» *Mom,* Go«r^K» -e«B^-vund«!r ^resf-i den^.B^Oe-Jt-^^^rjigiE^^te:
It is Very shameful.- {Jfw*aw«ptions>

[Shri V. Gopalsamy] What are you waiting for? Elections should be held there immediately. You are just waiting like a fisherman expecting t_0 catch a big fish. The point **is,** article 356 should be deleted form i the Constitution. Then only the spirit of federalism can be protected in the Country. *{Interruptions)* I said it, whichever Party comes and sits in power, it is tempted to use this article. Sir. when this article was debated in the Constituent Assembly, the great H. V. Kamath said 'It is one of shame and sorrow for the country'- *(Time bell rings)*

Therefore, once again, I would like *to* emphasise that elections should be held immediately in Goa. Suspended animation means suspense as if it is a crime thriller; which Party will kidnap how many MLAs. Therefore, political parties and Parliament should come to a final conclusion and delete this article, article 356, from the Constitution, to protect **th$_e$** unity and integrity of the **country.** Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA); Before I call the next speaker, j want to take the sense of the House. At 6 p. m. there is sp-ing to be a statement by the Minister of Railways. Therefore, I want to take the sense of the House whether v/e should sit beyond 6 p. m. or not.

SOME HON. MEMBERS; No.

SHRI M. M. JACOB: Sir, the Minister of Home Affairs can certainly five the reply tomorrow. The Railway Minister can make the statement at 6 p. m. and after that, the House may kindly be adjourned.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA); Shrimati Bijoya Chakravarty.

SHRI V. GOPALSAMY; I thank Mr. Jacob for making a good suggestion. (Interruption*)

SHRIMATI BIJOYA CHAKRA-VART (Assam); Mr. Vice-Chairman, Sir, democracy has been murdered in th$_e$ country by the Centre stalling the democratic process in different States and denying to the people their basic right. Therefore, I request thg hon. Minister sitting. here, —who is now busy talking, —to start the electoral process in Goa as early as possible,
thereby stopping the political corruption in the country.

With these words, I oppose the imposition of President's Rule in Goa and I once again demand that elections should be held there as early ag possible.

SHRISANTOSH BAGRODIA (Rajasthan); Sir, I rise to support the Resolution moved bv the hon. Minister of State for Home Affairs.

After listening to my friends on the other side. *I* feel that there are some people, there are some leaders, who would like to oppose just for the sake of opposition, i heard what Mr. Gopalsamy said. He said 'We do not want *aya rams and gaya rams. I* would like to point out to him that it was the Congress Party, under the leadership of Shri Rajiv Gandhi, which brought in the anti-defection Bill.
Who brought forward the anti-defection Bill? It was Mr. Rajiv Gandhi. We do not want *aya rams and gaya rams.* Please tell me. How many people left the Congress during the last one year or so? The strength of 195 remained as it is. Whereas let rae tell you that various leaders from different parties in the country have made a beeline to join the Congress party and still they are making the f beeline. So, there is no defection on our side and it is very sad to blame that the Congress party is interested in defections. (Interruptions)

6. 09 **P. M.**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA); The Minister of State for Railways has to make the statement. You can continue tomor row,

SHRj SANTOSH BAGRODIA; I will continue tomorrow.

STATEMENT BT MINISTER—TRAIN ACCIDENT ON BUDGE-BUBGE—SEALDAH- 'SECTION ON THE ' 6TH JANUARY, 1991

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भ त चरण दास) : महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ सदन में यह सूचित करना पड़ रहा है कि कल 6 जनवरी 1991 को 10 बजकर 26 मिन्ट पर एन जी 45 बज-बज सियालदाह ई०एम०यू० लोकल ट्रेन और गुड्स ट्रेन के बीच टक्कर के कारण सियालदाह में एक्सीडेंट हो गया जिसमें 9 लोग घायल होकर मर गए जिस में 5 पैसेंजर्स और 3 आफिशियल्स शामिल थे।

सियालदाह के डी आर एम० को इसकी जानकारी मिलने के पश्चात् वे वरिष्ठ अधिकारियों तथा मेडिकल टीम सहित तुरंत वहां पहुंचे। रिलीफ वगैरह की व्यवस्था करने के लिए ईस्टर्न रेलवे के विभागाध्यक्ष भी वहां पहुंचे और तुरंत रिलीफ की व्यवस्था की गई।

घायल यात्रियों में से दो लोगों को बी०आर० सिंह रेलवे अस्पताल में रखा गया और तीन लोगों को आर०के० मिशन अस्पताल में रखा गया और एक व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया।

यह घटना बहुत ही दुखद है। इस घटना की जांच के लिए माननीय रेल मंत्री महोदय श्री मिश्रा जी और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आज एक घंटे बाद यहां से रवाना होंगे और कल वहां पहुंचकर इसकी जांच करेंगे।

एक्सीडेंट में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को एक्स-ग्रेशिया पेमेंट तुरंत दिया जा रहा है। कमिश्नर आफ रेलवे सेफ्टी सुबह से सांविधिक जांच करने में लगे हुए हैं।

दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं और उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ उन लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करें।

SHSI MD. SALIM (West Bengal): Mr. Vi ce-Chairman, Sir, the south section of the Sealdah Division of the Eastern Railway is one of the most ' neglected sections in the Eastern Railway, and there is a long-standing demand for modernization of the signal system in the south section, particularly, in the intersection where this accident occurred la. st night.. The Budge Budge section and the Sonapur section are divided near the place of the accident. I would like to ask the Minister whether the Government' is ready to take corrective measures for a permanent solution to minimize chances of recurrence of such accidents.

Secondly, how, in the same line, do the goods train and the EMU train meet together? I would like t_0 know whether an inquiry has already been ordered into that. My point of concern is this: In such accidents, the authorities usually blame the staff on duty, but I would like to emphasize oil the point of maintenance. I want to know whether maintenance is being done regularly and what is the role of lack of such maintenance in thi_s particular, accident.

I also want to know whether the railway authorities have already taken steps to conpensate the families of the deceased persons and those who were injured and are under treatment now. I want to know whether the railway authorities have already taken a decision to compensate these people. Particularly, the time of the accident suggests that most of the victims **are** daily wage earners. Without going into details, as a Member from the city of Calcutta itself, I can gay that most of the victims are those travellers who are daily wage earners like vendors who used to go to the city